सोने मे तेजी, चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। सर्राफा बाजार में बीते सप्ताह सोने की कीमत सुधार के साथ 30,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रही हालांकि औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के कम उठाव के कारण चांदी की कीमत गिरावट रही। सर्राफा व्यापारियों ने कहा कि विदेशों में मजबूती के रुख और घरेलू हाजिर बाजार में शादी विवाह के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की लिवाली लिवाली बढने् के कारण मुख्यत- सोने के दाम में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना सप्ताहांत में तेजी दर्शाता 1,274.90 डॉलर प्रति औंस और चांदी तेजी के साथ 16.86 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

अगले चीनी सीजन में भारी उत्पादन!

नई दिल्ली12 नवम्बर (ए)। भारतीय चीनी उद्योग के एक वर्ग का कहना है कि चीनी वर्ष 2018-19 में चीनी उत्पादन 290 से 300 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहने की संभावना है। चीनी वर्ष 2018-19 अगले साल अक्तूबर से शुरू होगा। यह अनुमान कुछ राज्यों में गन्ने की खड़ी फसल और किसानों के बुआई के इरादे पर आधारित है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो यह न केवल भारत में किसी एक वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन होगा बल्कि यह 2017-18 के उत्पादन स्तर से करीब 40 से 50 लाख टन अधिक रहेगा। चीनी वर्ष 2017-18 में उत्पादन 250 लाख टन रहने का अनुमान है।

कावासाकी निंजा 650 का KRT एडिशन भारत में लांच

जालंधर 12 नवम्बर (ए)। भारत में जापानी मोटरसाइकिल निर्माता कावासाकी ने नई निंजा 650 के केआरटी एडिशन को लांच कर दिया है। इस नई बाइक की दिल्ली के एक्स-शोरूम के हिसाब से कीमत 5.69 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि केआरटी मॉडल की डिलीवरी इस महीने के अंत तक शुरू होगी। मोटरसाइकिल 649 सीसी का इंजन दिया गया है जोकि 67 बीएचपी पर 65.7 एनएम के टॉर्क को प्रोड्यूज करता है । कंपनी ने इस नई बाइक को 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। 2017 कावासाकी निंजा 650 नए लाइटर फ्रेम पर आधारित है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 22 किलो हल्का है। इसके अलावा निंजा 650 के सामने 300 मिमी ड्यूल डिस्क और पीछे220 मिमी डिस्क है। वहीं बाइक में एबीएस तकनीक और शानदार सस्पेंशन को शामिल किया गया है।

प्याज का एक्सपोर्ट 56% बढ़ा, फिर भी विदेश से पूरी हो रही है घरेलू डिमांड

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। देश में प्याज को लेकर अजीब-सी स्थिति है। एक तरफ भारत का प्याज एक्सपोर्ट इस साल अप्रैल-जुलाई के दौरान 56 फीसदी बढ़कर 12.29 लाख टन हो गया, वहीं दूसरी ओर देश में घरेलू डिमांड पूरी करने के लिए सरकार प्याज इम्पोर्ट कर रही है। सरकार का कहना है कि प्याज की खुदरा कीमतें 65-70 रुपए प्रति किलो हो गई हैं, इसलिए सप्लाई बढ़ाने और कीमतें काबू करने के लिए ऐसा जरूरी है।

वैल्यू के हिसाब से बात करें तो अप्रैल-जुलाई 2017 के दौरान प्याज का एक्सपोर्ट 47.69 फीसदी बढ़कर 1,443.09 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 977.84 करोड़ रुपए था। दूसरी ओर, पिछले सप्ताह सरकार ने स्त्र्ञ्च्रठ्ठ जैसी सरकारी एजेंसियों को मिस्र और चीन जैसे देशों से प्याज इम्पोर्ट करने के लिए कहा है। सरकार ने प्राइवेट ट्रेडर्स को भी प्याज इम्पोर्ट की सुविधा दी थी, जिन्होंने अबतक 11,400 टन प्याज विदेशी मार्केट से खरीदा है।

क्या कहते हैं आंकड़े

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैट्सिटिक्स के अनुसार, 2017-18 के अप्रैल-जुलाई के दौरान देश ने 12.29 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट किया। यानी, दूसरे देशों को बेचा। 2016-17 के इसी अवधि की बात करें तो उस समय देश से प्याज का एक्सपोर्ट 7.88 लाख टन था।

क्यों बढ़ा एक्सपोर्ट

नेशनल होर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के एक्टिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता का कहना है कि अप्रैल-जुलाई के दौरान प्याज का एक्सपोर्ट दो कारणों से बढ़ा है। पहला, प्याज पर कोई भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस नहीं था। दूसरा, ग्लोबल बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई थीं।उनका कहना है कि एक्सपोर्ट से चालू फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वाटर में किसानों को अपने प्रोडक्ट का बेहतर दाम मिला, जब घरेलू बाजार में कीमतें गिरी थीं। हालांकि, पुराना स्टॉक खत्म होने के साथ ही घरेलू मार्केट में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ष्ठत्रद्रस् के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई 2017 के दौरान एक्सपोर्टर्स को 11,737 रुपए प्रति टन का भाव मिला।

बता दें, एमईपी वह प्राइस होता है, जिससे कम पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। प्याज से एमईपी दिसंबर 2015 में ही हटा दी गई। अगस्त में डिमांड के बावजूद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने एमईपी नहीं लगाई। यह वहीं समय था जब घरेलू मार्केट में प्याज की कीमतों में तेजी शुरू हुई।

घरेलू बाजार में क्यों बढ़े दाम

पीके गुप्ता का कहना है कि घरेलू मार्केट में कीमतें अचानक बढ़ने की अहम वजह पुराना प्याज का स्टॉक समाप्त हो जाना और नई खरीफ फसल की आवक कम होना है। देश में कुल प्याज फसल का 40 फीसदी उत्पादन खरीफ सीजन में होता है। हालांकि, खरीफ फसल को स्टोर नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात प्याज पैदा करने वाले देश के प्रमुख राज्य हैं।

मिनिस्ट्री के आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में अप्रैल में रिटेल बाजार में प्याज की कीमत 15 रुपए प्रति किलो थी। जुलाई में यह धीरे-धीरे बढ़कर 35 रुपए प्रति किलो तक हो गए और अक्टूबर अंत तक यह भाव बढ़कर 50 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। लोकल वेंडर क्वालिटी के हिसाब से 70 रुपए प्रति किलो तक प्याज दिल्ली में बेच रहे हैं।

लोकल सप्लाई बढ़ाने के लिए हो रहा इम्पोर्ट

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, लोकल सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने प्राइवेट ट्रेडर्स के जरिए प्याज इम्पोर्ट की सुविधा दी थी, जिन्होंने अबतक विदेशी मार्केट से 11,400 टन प्याज खरीदा है। मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने बताया कि नई खरीफ फसल इस साल 10 फीसदी कम रह सकती है क्योंकि बुवाई में 30 फीसदी कमी देखी गई है।

एअर इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से मिला 1500 करोड़ का लोन, 3 माह में 2 सरकारी बैंकों ने दिया कर्ज

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। भारी कर्ज में डूबी एअर इंडिया को बड़ी राहत मिली है। सरकारी एयरलाइंस को तत्काल के आवश्यक खर्चों (वर्किंग कैपिटल) के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 1500 करोड़ रुपए का लोन मिल गया है। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया ने इस संबंध में टेंडर जारी किया था और एक माह से भी समय में उसे यह लोन मिल गया। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरा मौका है जब एअर इंडिया को सरकारी बैंक से लोन मिला है।

एअर इंडिया कई तरह की दिक्कतों से जूझ रही है। सरकार एयरलाइन में डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। वहीं, एअर इंडिया कंपनी कर्ज घटाने के लिए कई तरह के कदम उठाए रही है, जिसमें नॉन कोर एसेट की बिक्री और ऑपरेशंस का एक्पेंशन शामिल है। सूत्रों के अनुसार , पिछले महीने सरकारी एयरलाइंस ने तत्काल वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए लोन टेंडर जारी किया था, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 1500 करोड़ रुपए का लोन दिया। इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। एयरलाइन की तरफ से 18 अक्टूबर को टेंडर जारी किया गया, जिसमें सरकार से गारंटीड शॉर्ट टर्म लोन मांगा गया था।

दो बैंक पहले दे चुके हैं3,250करोड़ का कर्ज: इससे पहले, एअर इंडिया को 3,250 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन दो बैंकों इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से मिला था। यह लोन भी तत्काल वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए लिया गया है। इसके लिए टेंडर सितंबर में जारी किया गया था।

तीन महीने में दोसरकारी बैंकों से मिला लोन: पिछले तीन महीने की बात की जाए तो, कम से कम दो सरकारी बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने एअर इंडिया को लोन उपलब्ध कराए हैं। बीमारू एविशएशन कंपनी के रिवाइवल के लिए सरकार उसके स्ट्रैटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगभग फाइनल करने वाली है। बता दें, एअर इंडिया पर 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है।

टैक्सपेयर्स के पैसे पर चल रही है कंपनी: पिछली यूपीए सरकार ने 2012 में एअर इंडिया का बैलआउट पैकेज एक्सटेंड किया था। यानी कंपनी टैक्सपेयर्स के पैसे पर ही चल रही है। टर्नअराउंड प्लान के तहत, एअर इंडिया को 30,231 करोड़ रुपए तक की रकम अगले 10 साल में सरकार से मिलती रहेगी। इसमें शर्त यह है कि कंपनी को कुछ तय मानकों पर परफार्मेंस बेहतर देना होगा। एअर इंडिया ग्रुप 44 विदेशी और 75 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस पर उड़ानें ऑपरेट करती है।

RCom को एक और झटका ,चौथे क्वार्टर में 2709 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। लंबे समय से कर्ज की समस्या से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को एक और झटका लगा है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी को सितंबर, 2017 में समाप्त क्वार्टर के दौरान 2,709 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड लॉस हुआ है। वहीं एक साल पहले समान अवधि के दौरान कंपनी को 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। आरकॉम के लिए यह लगातार चौथा क्वार्टर है, जब उसे नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं कंपनी की कुल इनकम में भी भारी कमी दर्ज की गई। फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर के दौरान कंपनी की कुल इनकम 48 फीसदी गिरकर 2,667 करोड़ रुपए रह गई, जबकि बीते साल समान क्वार्टर के दौरान उसकी इनकम 5,142 करोड़ रुपए रही थी। वॉयस कॉल सर्विस को बंद करने के कगार पर खड़ी आरकॉम को भारतीय और ग्लोबल दोनों ऑपरेशन से रेवेन्यू में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर, 2017 में समाप्त क्वार्टर के दौरान कंपनी को टैक्स पूर्व 1,669 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जबकि बीते साल समान क्वार्टर के दौरान 611 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 45 हजार करोड़ रुपए के बोझ से दबी कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़कर 1,149 करोड़ रुपए हो गई, जबकि बीते साल समान क्वार्टर के दौरान यह आंकड़ा 825 करोड़ रुपए रहा था।

डिब्बाबंद उद्योग के समर्थन में पीएमओ, आर.एस.एस. की संस्था मायूस

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने केन्द्रीय स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास मंत्रालय की इस दलील को रद्द कर दिया है कि बच्चों को केवल पका हुआ खाना ही दिया जाए। इसके बाद डिब्बाबंद भोजन उद्योग खुश है। नैस्ले और अन्य बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अलावा आई.टी.सी. और रामदेव की पतंजलि जैसे घरेलू प्रमुख ब्रांड भी पी.एम.ओ. के इस फैसले से लाभान्वित होंगे। पी.एम.ओ. ने राज्यों का साथ दिया है जो इस बात पर अडिग है कि बच्चों को डिब्बाबंद भोजन दिया जाए। केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के बीच यह लड़ाई है कि बच्चों को कैसा भोजन दिया जाए। राज्यों के साथ लंबी चर्चा के बाद विश्लेषक समिति की रिपोर्ट और संबद्ध मंत्रालयों के विचारों को प्राप्त करने के बाद पी.एम.ओ. ने फैसला किया है कि राज्यों को इस संबंधी अपनी नीति का फैसला करने की अनुमति दी जाए। अगर राज्य सरकारें डिब्बा बंद भोजन देना चाहती हैं तो वे ऐसा करें। पी.एम.ओ. ने स्पष्ट रूप से कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है।

स्मार्टफोन से 2.5 गुना क्षमता वाला खरीदें पावरबैंक, नहीं तो चार्जिंग में होगी मुश्किल

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। बढ़ते समय के साथ जितनी तेजी के साथ स्मार्टफोन के फंक्शन बढ़ रहे हैं, उनकी बैट्री पर दबाव भी उतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले एक बार चार्ज होने के बाद बेसिक फोन 2 से 3 दिन तक चल जाते थे। अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनकी बैट्री का दिन भर भी टिकना मुश्किल हो गया है। ऐसे दौर में पावर बैंक एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। एक सर्वे के मुताबिक, स्मार्टफोन करने वाला हर तीसरा व्यक्ति पावर बैंक का यूज करता है। हम जब भी पॉवरबैंक खरीदने जाते हैं तो यह कोशिश करते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा mAh का हो। हालांकि सिर्फ यही देखना काफी नहीं होता है। पावरबैंक में कुछ और भी चीजें होती हैं, जिन्हें खरीदते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए।

अमूमन हम पावरबैंक का यूज तब करते हैं, जब हमें कहीं घूमने जाना हो। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां आप अपनी डिवाइस या गैजेट को चार्जर से नहीं चार्ज कर सकते हैं, तब भी हम पावरबैंक का यूज करते हैं। इसलिए जब भी पावरबैंक खरीदें तो अपनी जरूरत का जरूर ख्याल रखें। अगर आपके पास सिर्फ एक ही डिवाइस है तो कम क्षमता वाला पावरबैंक खरीद सकते हैं। अगर कई डिवाइस हैं तो ज्यादा क्षमता वाला पॉवरबैंक खरीदें।

किसी भी पावरबैंक की क्षमता उसकी कैपेसिटी के आधार पर तय होती है। इसे द्धद्ध यानी मिली एम्पियर आवर कहा जाता है। इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, पर जितना ज्यादा mAh होगा पावरबैंक की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। टेक एक्सपर्ट अजेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, आपको पावरबैंक आपकी बैट्री से 2.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके फोन की बैट्री 4000 द्धद्ध की है तो आपके फोन को चार्ज करने में पावरबैंक की करीब 6700 द्धद्ध की बैट्री जाएगी। ऐसे में अगर बराबर की क्षमता का चार्जर लेंगे तो वह आपके के लिए बेहतर आउटपुट नहीं देगा। हमेशा पावरबैंक में आउटपुट वोल्टेज का जरूर खयाल रखें। अगर आपके पावर बैंक का आउटपुट वोल्टेज आपके फोन चार्जर के आउटपुट वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पावरबैंक आपके फोन चार्जर को चार्ज नहीं कर पाएगा। साथ ही वह आपके फोन चार्जर से चार्ज भी नहीं होगा। मॉडर्न पॉवरबैंक तो यूएसबी चार्जिंग से लैस आते हैं, लेकिन मार्केट में आने वाले कुछ ओल्ड एज पॉवरबैंक में उनकी अपनी केबल काम करती है। ऐसे पॉवरबैंक आपके डिवाइस के लिए फिट नहीं होंगे।

जीएसटीः फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री नाराज, कहां 20 प्रतिशत नौकरियां खतरे में

नई दिल्ली 12 नवम्बर (ए)। शुक्रवार को जी.एस.टी. काऊंसिल के फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री निराश है। उसके अनुसार काऊंसिल ने ऐसे कोई बड़े फैसले नहीं किए हैं जिससे सुस्ती से जूझ रही इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। इंडस्ट्री के अनसार टूरिज्म सैक्टर में 20 प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां खतरे में हैं। इस फैसले से इन पर सीधा नैगेटिव इम्पैक्ट होगा।

टूरिज्म सैक्टर को नहीं मिली राहतः इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑप्रेटर (आई.ए.टी.ओ.) के प्रैसीडैंट प्रणब सरकार ने बताया कि सरकार ने टूरिज्म सैक्टर को कोई बड़ी राहत नहीं दी है। सरकार ने 7500 रुपए से ज्यादा रैंट वाले होटलों पर आई.टी.सी. सहित 18 प्रतिशत टैक्स कर दिया है जो पहले 28 प्रतिशत था। सरकार अब पुराने वाले लैवल पर टैक्स रेट ले आई है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पडने् वाला है क्योंकि क्रिसमस और नए साल के लिए ज्यादा टैक्स रेट के कारण इंडिया में फाइव स्टार होटल की बुकिंग ज्यादा नहीं हुई है। इससे टूरिज्म सैक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि होटल के टैक्स लगाने के बाद वह पैकेज पर अलग 5 प्रतिशत टैक्स लगाते हैं। पैकेज में सर्विस जुडने् से टैक्स बढ़ जाता है और इसका नैगेटिव असर पड़ रहा है।

इंडियन टूरिज्म सैक्टर नहीं रहा कम्पीटीटिवः इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर पड़ोसी देशों के मुकाबले कम्पीटीटिव नहीं रहा है। बल्क कॉर्पोरेट बुकिंग इंडिया की जगह म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों को मिल रही है जहां टैक्स 5 से 10 प्रतिशत की रेंज में है। देश का जटिल टैक्स स्ट्रक्चर और ज्यादा जी.एस.टी. रेट टूरिज्म सैक्टर को नुक्सान पहुंचा रहा है क्योंकि कम्पनियों की बुकिंग कम हो चुकी है।

नाखुश रैस्टोरैंट मालिकः जी.एस.टी. काऊंसिल ने 211 आइटम्स पर टैक्स स्लैब में कमी कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रैस्टोरैंट में खाने पर टैक्स में कटौती को लेकर है। अब रैस्टोरैंट में 18 की जगह 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। दरअसल काऊंसिल का कहना है कि रैस्टोरैंट इनपुट टैक्स क्रैडट (आई.टी.सी.) का बैनिफिट कस्टमर्स को नहीं दे रहे थे, इसलिए इनपुट टैक्स क्रैडिट को वापस ले लिया गया है। वहीं, रेस्तरां मालिक काऊंसिल के इस फैसले से नाखुश हैं।

10 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं मैन्यू प्राइसः इनपुट टैक्स क्रैडिट के वापस लेने से नाराज कई रैस्टोरैंट के मालिक मैन्यू प्राइस में 10 प्रतिशत तक का इजाफा करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर्स को जी.एस.टी. के घटे स्लैब का फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि जब तक रैस्टोरैंट मालिक ऐसा निर्णय नहीं लेते, तब तक के लिए कस्टमर्स को इसका फायदा मिलेगा।

जीएसटी सुधारों से शेयर बाजार में दिख सकती है तेजी

मुंबई 12 नवम्बर (ए)। मुनाफा वसूली और कुछ बड़ी कंपनियों में बिकवाली के दबाव में बीते सप्ताह बी.एस.ई. के सैंसेक्स में 1.1 प्रतिशत यानी 371 अंक की गिरावट के साथ 33,314.56 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.25 प्रतिशत यानी 130.75 अंक लुढ़ककर सप्ताहांत पर 10,321.75 अंक पर आ गया। मझौली और छोटी कंपनियों में भी गिरावट रही। बी.एस.ई. का मिडकैप 0.9 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट में 16,562.69 अंक पर और स्मॉलकैप 1.19 प्रतिशत उतरकर 17,643.82 अंक पर बंद हुआ। आने वाले सप्ताह में बाजार की चाल महंगाई के आँकड़ों और तिमाही परिणामों पर निर्भर करेगी लेकिन, सबसे ज्यादा असर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दिशा में जीएसटी परिषद द्वारा शुक्रवार शाम की गयी घोषणाओं का दिखेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाजार में अच्छी तेजी देखी जा सकती है।